[श्री विनायक प्रसाद यादव]

मांगो की ओर मुखाविध होने की बजाय पुलिस टेरर करवा रही है, जिस के चलते शिक्षक में दायो मे जबर्दस्त विक्षोप पैदा हो रहा है और वे अपना आन्दोलन उग्र करने पर मजबूर किये जा रहे हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री का यह बयान कि शिक्षको की धमकी से वे डरने वाले नही हैं, देख कर आश्चर्य और दुःख हुआ है। गरीब शिक्षक धमकी देने की स्थिति में नही है, न वे धमकी देना चाहते है। गरीबी की मार से तबाह हो कर अपनी जायज मांगें शांतिपूर्वक ढग से रख रहे है।

अत: मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए, उन की मागो के सम्बन्ध में वक्तव्य की माग करता हू।

(iv) FUNCTION ORGANISED IN HONOUR OF THE SOVIET PRIME MINISTER UNDER AUSPICES OF INDO-SOVIET CULTURAL SOCIETY.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हू।

यह दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय अतिथि सोवियत रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन के सुआगमन पर भारत रूसी मैत्री संघ (इसकास) के तत्वाधान में आयोजित सभा को राजनीतिक रगमच बना दिया गया। 10 मार्च को आयोजित इस बैठक मे सोवियत रूस के प्रधान मत्री के ममक्ष श्री राजेश्वर राव और श्री शकर दयाल सिंह न कम्पूचिया को मान्यता नहीं देने के बारे मे भारत सरकार की तीव्र भर्त्सना की और विदेश मत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा की भी प्रखर आलोचना की।

मैं यह नही कहता कि हमारी विदेश नीति की हमारे बन्धु आलोचना न करे लेकिन किसी विदेशी मेहमान के स्वागत में आयोजित सभा में उनके सामने यह इस प्रकार की बाते करना राष्ट्र के स्वाभिमान पर कलक तथा साथ ही साथ स्वय देश की एकता का भी हृदय विदारक चित्र उपस्थित करता है। कुछ ही दिनों पहले भारत मे सोवियत समर्थक 14 देशो के राजदूतों ने एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस करके चीन अथवा वियतनाम के हमले की निन्दा की थी।

प्रत्येक देश किसी भी मामले पर अपनी नीति निर्धारित करने का पूर्ण अधिकारी है। लेकिन हमारी धरती पर इस प्रकार की संयुक्त बयानबाजी और राजनीतिक पेचकश भारत की सार्वभौमिकता का समादर नही है। अगर सरकार इन चीजों के सम्बन्ध में अभी से ध्यान नहीं देती, तो बढ़ते-बढ़ते छोटा सा फोड़ा भारी भगन्दर का रूप धारण कर लेगा और भारतवर्ष में विदेशी राजनीति की दखलान्दाजी घर कर जाएगी।

इसलिए मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हू कि भविष्य मे ऐसे किसी भी संस्था या सघ को विदेशी मेहमानो के स्वागत सत्कार के लिए अनुमति न दी जाये जो इसको गुटपरस्ती और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जोड़ तोड़ का अखाड़ा बना देती है और विभिन्न देशो के राजदूत को भी यह स्पष्ट कह दिया जाये कि इस प्रकार की संयुक्त बयानबाजी और प्रेस कान्फ्रेंस आदि भारत की भूमि पर न की जाए।

(v) THE JOINT STATEMENT ISSUED BY PRIME MINISTERS OF INDIA AND THE SOVIET UNION.

श्री राज नारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, हमारे कुछ आर०एस०एस० के मित्र हम को पीछे आने को कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात स्टेटमेंट मे नही है।

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं आप के पुकारने पर तत्काल नही उठा, इसलिए स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

श्रीमन्, लोक सभा के प्रक्रिया कार्य तथा सचालन विषयक नियमों के नियम 377 के अधीन मैं निम्न महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुनियेगा क्योंकि अभी डा० साहब जो बोले है, शायद हमारी ध्वनि उस से कुछ विपरीत जाए।

गत 15 मार्च, 79 को भारत-रूस के प्रधान मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान द्वारा चीन को बिना किसी शर्त तत्काल वियतनाम से पूर्णरूपेण चीनी सेना को हटा लेने को कहा है। इस संयुक्त वक्तव्य में एग्रेशन (हमला) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक रहस्य है क्योंकि श्री कोसिजिन बराबर एग्रेशन शब्द का प्रयोग करते थे। इस से ऐसा लगता है (व्यवधान)। श्रीमती गाधी पूछते हैं कि एग्रेशन और आक्रमण में क्या फर्क है।

एक माननीय सदस्य : हमले और आक्रमण में ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्टेटमेंट में से पढ़िये।

श्री राज नारायण : एग्रेशन का मतलब क्या है ? आप जज रह चुके हैं ? अगर कोई आक्रमण करता है तो प्रोवोकेशन से करता है अगर कोई एग्रेशन करता है तो बिना किसी प्रोवोकेशन के करता है। एग्रेशन को हमने हमला कहा है और अटैक को हमने आक्रमण कहा है। वियतनाम ने चीन प्रोवोक नहीं किया था।

यह एक रहस्य है क्योंकि श्री कोसिजिन बराबर एग्रेसन शब्द का प्रयोग करते थे उससे ऐसा लगता है कि भारत चीन को एग्रेसर कहना पसन्द नहीं करता। जब कि वास्तव में चीन एग्रेसर है। हम यह भी रहस्य जानना चाहते हैं कि जब भारत की सरकार ने वियतनाम से चीनी सेना को अविलम्ब पूर्ण रूपेण हटाने की मांग की तो भारत की ओर से, भारत की पवित्र भूमि से चीनी हमले को पूर्ण रूपेण खत्म करने की बात क्यों नहीं की गई जिससे लद्दाख उत्तर पूरब अंचल तथा निर्बन सभी जगहों से चीन अपनी सेना वापस बुलाने और निर्बत की पवित्र भूमि खाली कर दे। मैं भारत की सरकार से इस का स्पष्टीकरण चाहूंगा, और चाहूंगा कि चीनी हमले पर पूरी बहस हो। हमें मालूम है कि विदेश मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति तीनों ने समय समय पर विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। किसी ने एग्रेशन कहा है और किसी ने आक्रमण कहा है इसलिए जनता में भ्रम फैला है कि भारत की सरकार की इस सम्बन्ध में एक राय नहीं है, सरकार स्वयं में विभाजित है। (व्यवधान)।

(Interruptions)

MR SPEAKER: Don't record.

(Interruptions) **

12.33 hrs.

MIZORAM BUDGET, 1979-80—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (MIZORAM), 1979-80, AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MIZORAM), 1978-79

MR. SPEAKER: The House will now take up (i) General discussion on the Budget for the Union territory of Mizoram for 1979-80, (ii) discussion on the Demands for Grants on Account in respect of the budget for the Union territory of Mizoram for 1979-80 and (iii) discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget for the Union territory of Mizoram for 1978-79 All the three items are to be discussed together

If the House agrees, two hours may be allotted for discussion of these items as suggested by the Government I suppose the House will agree.

HON. MEMBERS: Yes.

MR SPEAKER: Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Mizoram, *on account*, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1980, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 41."

Demands for Grants on Account (Union Territories of Mizoram) for 1979-80 submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on Account Submitted to the vote of the House.	
1	2	3	
		Revenue Rs.	Capital Rs
1.	Legislative Assembly	5,25,000	.
2.	Administrator	27,000	.
3.	Council of Ministers	2,40,000	..
4.	Administration of Justice	4,66,000	..

**Not recorded